University in News on 30 March 2023

HINDUSTAN PAGE 6

एलयू: इंक्यूबेशन सेन्टर को मंजूरी, 1.5 करोड़ मिलेंगे

लखनऊ। एलयू के इंक्यूबेशन सेन्टर को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे अब विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही छात्रों को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर है कि एलयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सेन्टर के निदेशक प्रो. अमृतांशु शुक्ल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्टार्ट अप के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर के प्रचलन व्ययों की पूर्ति के लिए पांच वर्षों की अवधि तक के लिए 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं।

विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना से लाइब्रेरी, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, कैंटीन, पुस्तकालय के साथ तकनीकी मदद आसानी से मिल जाती है। प्रो. अमृतांशु ने बताया कि नव उद्यमियों को अपने बिजनेस को विकसित करने के लिए समय-समय पर नई तकनीकी जानकारी, उपकरण व प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्टार्ट अप के लिए पैसा कहां से जुटाएं तथा कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाती है।

इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। प्रो. अमृतांशु ने बताया कि सेंटर से विश्वविद्यालय से बाहर के लोग भी जुड़ सकते हैं बशर्ते उनकी कंपनी का प्रमुख कार्यालय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हो।

"इंक्यूबेशन सेंटर से जुडी सेक्शन-8 कंपनी नवांकुर फाउंडेशन के चेयरमैन कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय हैं। उन्होंने निरंतर एलयू से जुड़े सभी छात्रों व शिक्षकों को शोध और नवाचार को स्टार्ट अप के स्तर तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। **प्रो. पूनम टंडन**
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं अकादमिक

सीएसबी संग एमओयू से इंटर्नशिप करेंगे छात्र

एलयू के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक डॉ. सत्यनारायण ने बुधवार को केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) कपड़ा मंत्रालय, बेंगलुरु और एलयू के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जंतु विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। वे इंटर्नशिप कर सकेंगे।

एलयू में कुलपति प्रो. आलोक राय ने बुधवार को लॉ फेस्ट का अनावरण किया।

कुलपति ने लॉ फेस्ट के पोस्टर का किया अनावरण

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने बुधवार को सात से नौ अप्रैल के बीच होने वाले फर्स्ट नेशनल लॉ फेस्ट के पोस्टर का अनावरण किया। यहां कुलपति ने कहा कि विधि संकाय की ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजाल्यूशन एंड ड्राफ्टिंग सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा पहला 'नेशनल लॉ फेस्ट' अभूतपूर्व होगा।

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

रेशम बोर्ड व लविवि के बीच एमओयू

लखनऊ। केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय बेंगलूरू और लखनऊ विवि के बीच बुधवार को एमओयू किया गया। यह एमओयू लविवि के कुलपति प्रो. आलोक राय और सीटीआर एंड टीआई के निदेशक डॉ. के सत्यनारायण के बीच हस्ताक्षरित हुआ। कुलपति ने कहा कि यह समझौता नई शिक्षा नीति के तहत संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ ही कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता करेगा। जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. सेराजुद्दीन भी मौजूद रहे। (संवाद)

लविवि : इंक्यूबेशन सेंटर को सरकार की मंजूरी

लखनऊ। लविवि के इंक्यूबेशन सेंटर को बुधवार को यूपी सरकार से मान्यता मिल गई। यह जानकारी विवि के प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के निर्देशन में वर्ष 2022 में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही सेक्शन 8 में नवांकुर फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। मान्यता के बाद सरकार की ओर से प्रतिवर्ष तीस लाख का अनुदान पांच वर्षों तक दिया जाएगा। इंक्यूबेसन सेंटर के निदेशक प्रो. अमृतांशु शुक्ला ने बताया कि सेंटर का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टार्टअप को मदद के लिए नीति बनाकर बजट में विशेष प्रावधान भी किया है। उन्होंने बताया कि सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि वे स्टार्टअप के लिए धन कहां से जुटाए और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी नवांकुर के चेयरमैन कुलपति आलोक कुमार राय हैं। (संवाद)

i-NEXT PAGE 5

इन्क्यूबेशन सेंटर को डेढ़ करोड़ का अनुदान

लखनऊ विश्वविद्यालय के इन्क्यूबेशन सेंटर के संचालन के लिए राज्य सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है. इनमें से प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए (पांच वर्षों की अवधि में) खर्च किए जा सकेंगे. सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 एवं शासनादेशों के तहत इसे मंजूरी दी है.बीते वर्ष इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही सेक्शन आठ कंपनी के रूप में नवांकुर फाउंडेशन स्थापना की गई थी. इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है. सेंटर के निदेशक प्रोफेसर अमृतांशु शुक्ल ने बताया कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप को मदद तथा प्रोत्साहित करने, युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाई है. वित्तीय बजट में भी विशेष प्रविधान किया है.

JAGRAN CITY PAGE III

विद्यार्थियों को मिलेगा सिल्क तैयार करने का प्रशिक्षण

लखनऊ: लवि ने बुधवार को केंद्रीय रेशम बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय बेंगलुरु के साथ एमओयू किया। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय और केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के निदेशक डा. के सत्यनारायण ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के माध्यम से शोधार्थियों एवं एमएससी जंतु विज्ञान के छात्र-छात्राओं को सिल्क तैयार करने संबंधी तमाम जानकारियां दी जाएंगी। (जासं)

इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए मिला डेढ़ करोड़ का अनुदान

जासं, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के इन्क्यूबेशन सेंटर के संचालन के लिए राज्य सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। इनमें से प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये (पांच वर्षों की अवधि में) खर्च किए जा सकेंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 एवं शासनादेशों के तहत इसे मंजूरी दी है।

THE PIONEER PAGE 3

LU to host Science Congress

Lucknow (PNS): Lucknow University Vice-Chancellor Prof Alok Kumar Rai said that the Lucknow University had been selected for hosting the 109th annual session of Indian Science Congress.

It is after 22 years that Uttar Pradesh has got the opportunity to host the science congress. It is worth mentioning that Lucknow University hosted Indian Science Congress in the year 2002.

"It is a matter of great pride and pleasure to have this immense responsibility bestowed upon us by the Indian Science Congress Association. This mega scientific global event is supposed to be held from January 3-7, 2024," the vice-chancellor said.

At least 20,000 delegates, including Noble laureates from across the globe, are expected to attend this conference.

Lucknow University has previously hosted the Indian Science Congress five times -- in 1916, 1923, 1953, 1985 and 2002.

Lucknow University has already begun preparations with initiation of assessment of resources required for hosting this epic science event.

INCUBATION CENTRE

The Incubation Centre of Lucknow University has received approval from the Uttar Pradesh government. Under the guidance of LU Vice-Chancellor Prof Alok Kumar Rai, the university is not only working to train students and make them job-ready by imparting employment-oriented education with the implementation of the National Education Policy 2020 but also is preparing the young generation to become job-givers through "Navankur". Under the guidance of Prof Rai, LU had established Navankur Foundation as a Section 8 company in 2022 with the establishment of the University Incubation Centre. The main objective of the Incubation Centre is to encourage startups and entrepreneurship while promoting research and innovation in the university.

PIONEER PAGE 3

लविवि के इनक्यूबेशन सेन्टर को मिली सरकार से मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेन्टर को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गयी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय के दिशा.निर्देशन में 2022 में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही सेक्शन 8 कंपनी के रूप में नवांकुर फाउंडेशन के स्थापना की गई थी। इनक्यूबेशन सेन्टर का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

इनक्यूबेशन सेन्टर के निदेशक प्रोफेसर अमृतॉशु शुक्ल ने बताया कि उत्तर प्रदेश मे स्टार्ट अप के लिए अनेक संभावनाएँ हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश सरकार ने इन्क्यूबेशन सेंटर के प्रचलन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्षों की अवधि तक के लिए 3 0 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड स्वीकृत किये हैं। यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 एवं तत्संबन्धी शाशनादेशों के तहत परिचालित होगी। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट अप को मदद मुहैया करवाने तथा प्रोत्साहित करने, युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाई है तथा प्रदेश सरकार के वित्तीय बजट में विशेष प्रावधान किया है। इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड स्टार्टअप को सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इनक्यूबेशन सेंटर एक प्रकार नवउद्यमियों के लिए एक प्रारंभिक मंच की तरह होता है।

एलयू व सीएसबी के बीच हुआ अनुबंध

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय और और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) कपड़ा मंत्रालय बेंगलुरु के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। अनुबंध पत्र पर विवि के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीटीआर एंड टीआई) रांची, झारखंड के निदेशक डॉ के सत्यनारायण ने किया। इस मौके पर सेराजुद्दीन, प्रो अमिता कनौजिया, डॉ जेपी पाण्डेय और डॉ जे बिनकादकट्टी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। समझौता ज्ञापन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने और कार्यक्रमों को निष्पादित करने में पारस्परिक सहायता की सुविधा प्रदान करेगा।

AMRIT VICHAR PAGE 4

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर करार

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआर एंड टीआई) रांची, झारखंड के निदेशक डॉ. के. सत्यनारायण ने केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) कपड़ा मंत्रालय, बेंगलुरु, कर्नाटक और लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रो. मो. सेराजुद्दीन, प्रो. अमिता कनौजिया, डॉ. जेपी पाण्डेय और डॉ. जे बिनकादकट्टी साक्षी के रूप में उपस्थित थे।

बता दें कि समझौता ज्ञापन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने और कार्यक्रमों को निष्पादित करने में पारस्परिक सहायता की सुविधा प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करेगा, यह वैज्ञानिकों, संकायों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

इनक्यूबेशन सेन्टर को मिली मंजूरी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

लविवि

- प्रदेश सरकार ने 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड़ स्वीकृत किए

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेंटर को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश सरकार ने इनक्यूबेशन सेंटर के प्रचलन व्ययों की पूर्ति के लिए 5 वर्षों की अवधि तक के लिए 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड़ स्वीकृत किये हैं।

बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के दिशा-निर्देशन में 2022 में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही सेक्शन 8 कंपनी के रूप में नवांकुर फाउंडेशन के स्थापना की गई थी। इनक्यूबेशन सेन्टर का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इनक्यूबेशन सेन्टर के निदेशक प्रो. अमृतांशु शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में स्टार्ट अप के लिए अनेक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश सरकार ने इनक्यूबेशन सेंटर के प्रचलन व्ययों की पूर्ति के लिए 05 वर्षों की अवधि तक के लिए 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड़ स्वीकृत किये हैं। यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के शासनादेश के तहत परिचालित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट अप को मदद मुहैया करवाने तथा प्रोत्साहित करने, युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाई है। प्रदेश सरकार के वित्तीय बजट में विशेष प्रावधान किया है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं डीन अकादमिक लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय इनक्यूबेशन सेंटर से जुड़ी सेक्शन 8 कंपनी नवांकुर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े सभी छात्रों एवं शिक्षकों को शोध एवं नवाचार को स्टार्टअप के स्तर तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

VOICE OF LUCKNOW PAGE 6

लविवि और सीएसबी के बीच समझौता

लखनऊ। लविवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआर एंड टीआई), रांची, झारखंड के निदेशक डॉ. के. सत्यनारायण ने केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) कपड़ा मंत्रालय, बेंगलुरु, कर्नाटक और लविव के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रो. मो. सेराजुद्दीन, प्रो. अमिता कनौजिया, डॉ. जेपी पाण्डेय और डॉ. जे. बिनकादकट्टी साक्षी के रूप में उपस्थित रहे। समझौता ज्ञापन नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने और कार्यक्रमों को निष्पादित करने में पारस्परिक सहायता की सुविधा देगा। समझौता ज्ञापन व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देगा।

लविवि के इनक्यूबेशन सेंटर को प्रदेश सरकार से मिली मंजूरी

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेंटर को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही छात्र-छात्राओं को न केवल रोजगारपरक शिक्षा देने का कार्य कर रहा है बल्कि नवांकुर के माध्यम से रोजगार देने वाली युवा पीढ़ी तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के दिशा-निर्देशन में 2022 में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही सेक्शन 8 कंपनी के रूप में नवांकुर फाउंडेशन के स्थापना की गयी थी। इनक्यूबेशन सेंटर का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय में शोध व नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

इनक्यूबेशन सेंटर के निदेशक प्रो. अमृतांशु शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप के लिए अनेक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त होने से प्रदेश सरकार ने इन्क्यूबेशन सेंटर के प्रचलन व्ययों की पूर्ति के लिए पांच वर्षों की अवधि तक के लिए 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल 1.5 करोड़ स्वीकृत किये हैं। यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 एवं तत्संबन्धी शासनादेशों के तहत परिचालित होगी।

प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को मदद मुहैया करवाने और प्रोत्साहित करने, युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनायी है और प्रदेश सरकार के वित्तीय बजट में विशेष प्रावधान किया है। इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड स्टार्टअप को सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। इनक्यूबेशन सेंटर एक प्रकार नव उद्यमियों के लिए एक प्रारंभिक मंच की तरह होता है, जो शुरूआती दौर में स्टार्टअप की संरचना तथा उसे आगे बढ़ने में उद्यमी की मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों के लिए एक सुगम वातावरण देना और जरूरी मदद एक ही स्थान पर मिलने से वे नये व्यवसाय की शुरूआत करते हैं और अपने स्टार्टअप की विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना से लाइब्रेरी, मीटिंग/कांफ्रेंस, कैंटीन, पुस्तकालय के साथ तकनीकी सहयोग आसानी से सुलभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त नव उद्यमियों को अपने बिजनेस को विकसित करने के लिए समय समय पर नई तकनीकी जानकारी, उपकरण व प्रशिक्षण के साथ ही यह बताया जाता है कि वे अपने स्टार्टअप के लिए पैसा कहां से जुटायें तथा नये आइडियाज के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बताते चलें कि स्टार्टअप के इनक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना तथा डीपिट प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसमें विश्वविद्यालय से बहार के लोग भी जुड़ सकते हैं बशर्ते उनकी कंपनी का प्रमुख कार्यालय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हो।

TRUE TIMES PAGE 2

कपड़ा मंत्रालय, बेंगलुरु और लखनऊ विश्वविद्यालय, के बीच हुआ समझौता

ट्रू टाइम्स संवाददाता

प्रोफेसर आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय और डॉ. के. सत्यनारायण, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सी.टी. आर. एंड टी.आई), रांची, झारखंड के निदेशक ने केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.). कपड़ा मंत्रालय, बेंगलुरु, कर्नाटक और लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रोमो, सेराजुद्दीन, प्रो. अमिता कनौजिया, डॉ. जे.पी. पाण्डेय और डॉ. जे. बिनकादकट्टी साक्षी के रूप में उपस्थित थे।

समझौता ज्ञापन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसंधान के - संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने और कार्यक्रमों को निष्पादित करने में पारस्परिक सहायता की सुविधा प्रदान करेगा।

समझौता ज्ञापन व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करेगा, यह वैज्ञानिकों, संकायों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा, परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करेगा समझौता ज्ञापन में प्रावधान है कि दोनों पक्ष दोनों संस्थानों में (प्रासंगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को साझा करेंगे।

HINDUSTAN TIMES PAGE 6

LU Incubation Centre gets govt approval

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The Incubation Centre of Lucknow University (LU) has received approval from the Uttar Pradesh government.

The main objective of the centre is to encourage startups and entrepreneurship while promoting research and innovation in the university, said vice chancellor Prof Alok Kumar Rai.

LU had established Navankur Foundation as a Section 8 company in 2022 for setting up the university incubation centre. Professor Amritashu Shukla, director of the centre, said there were many possibilities for startups in Uttar Pradesh. After being recognized, the state government has given a total grant of Rs. 5 crore. This approval will be operational under the Uttar Pradesh Startup Policy 2020 and related mandates.

> LU is preparing the young generation to become job-givers through 'Navankur'
> **PROFESSOR AMRITASHU SHUKLA,** centre director

Prof Rai said, "Lucknow University is not only working to train students and make them job-ready by imparting employment-oriented education with the implementation of the National Education Policy 2020, it is also preparing the young generation to become job-givers through 'Navankur'."

"The Uttar Pradesh government has formulated a special policy to provide assistance and encourage start-ups to increase entrepreneurship among the youth, and has made a special provision in its financial budget," Prof Shukla said adding, "Assistance is provided by the government to the registered startups through the Incubation Centre, which is like a starting platform for entrepreneurs, helping them to structure and grow the startup in the initial stages."

The objective is to provide a convenient environment for entrepreneurs and get the necessary help at one place to start new businesses and successfully take forward their startups growth plans, he said.

TOI PAGE 3

Govt nod to incubation centre of LU

Times News Network

Lucknow: Innovative ideas of Lucknow University students may not go wasted anymore as the varsity will soon come up with a platform to transform them into viable business propositions.

The state government has given approval to the University for its start-up incubation centre along with a fund of Rs 5 crore on Wednesday.

"LU is not only working to train students and make them job-ready by imparting employment-oriented education as part of National Education Policy 2020 but is also preparing the young generation to become job-givers," said dean student welfare Prof Poonam Tandon. "We have already started a new scheme 'Navankur' with an aim to promote innovation, research, incubation, entrepreneurship, education, sports, environment protection and start-up ideas of students as well as teachers. The main objective of the center is to encourage startups and entrepreneurship while promoting research and innovation.

Director of incubation centre Prof Amritashu Shukla, said, " The government has formulated a special policy toencourage startups."

Justice DK Upadhyaya is senior judge

Times News Network

Lucknow: Allahabad High Court Chief Justice Pritinker Diwaker on Wednesday appointed Justice Devendra Kumar Upadhyaya as Senior Judge of Lucknow bench and authorized him to exercise jurisdiction at Lucknow.

Earlier, Justice Ramesh Sinha was the senior judge, who on Wednesday was administered oath as the Chief Justice of Chhattisgarh high court.

DID LAW FROM LU

Justice Upadhyaya was born on June 16, 1965. He received the law degree from Lucknow University in 1991 and got enrolled as a lawyer with the UP Bar Council immediately .

He specialized in civil and constitutional matters during his legal practice. Justice Upadhyaya was appointed a judge of the Allahabad high Court on November 21, 2011.

He would hold sitting at Lucknow bench.

NBT PAGE 3

एलयू के इनक्यूबेशन सेंटर को मंजूरी

एनबीटी, लखनऊ : शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एलयू के इनक्यूबेशन सेंटर को मंजूरी दे दी। इनक्यूबेशन सेंटर के निदेशक प्रो. अमृतांशु शुक्ल ने बुधवार को बताया कि सेंटर को मंजूरी मिलने के बाद पांच साल के लिए डेढ़ करोड़ रुपये भी स्वीकृत हुए हैं जो हर साल 30-30 लाख रुपये में मिलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों के लिए एक सुगम वातावरण प्रदान करना है। इस सेंटर से बिजनेस को विकसित करने के लिए नई तकनीकी जानकारी, उपकरण और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसमें विवि से बाहर के लोग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी प्रमुख कार्यालय का यूपी में होना अनिवार्य है।